THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) It is estimated that 7.75 million ha. of wasteland have been afforested till June, 1986.

(b) The total amount allocated including States' share till the year 1986-87 is Rs. 1594.56 crores, that of which it is estimated that Rs. 1215 crores have been spent till June, 1986.

दक्षिण भारत में संसद के अधिवेशन का आयोजन

965. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या संसदीय कार्य मंत्री 4 मई, 1984 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 820 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की एकता को ध्यान में रखते हुए छह महीने के लिए संसद का अधिवेशन दक्षिण भारत (बंगलौर) में आयोजित करने का निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) अभी सरकार का दिल्ली से बाहर संसद के किसी सत्र के आयोजन का कोई विचार नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Failure of HAL to design combat Aircraft

966. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Hindustan Aeronautics Limited has failed to design a wholly Indian combat aircraft during the 30 years of its working;

(b) if so, the details of the projects regarding designing and manufacturing of combat aircraft taken up by Hindustan Aeronautics Limited; and

(c) by when a wholly Indian combat aircraft is likely to be produced by the Hindustan Aeronautics Limited?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND DEFENCE SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir.

(b) and (c) M/s Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) have indigenously designed and produced a combat aircraft, viz., HF-24 (Marut), which had been in service for more than 15 years. Presently HAL is a major participant in the project undertaken by the Aeronautical Development Agency for the design and development of a 'Light Combat Aircraft'.

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम

967. **श्री जगदंबी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा के प्रगामी प्रयोग का कार्यक्रम जो सभी मंत्रालयों, संस्थानों तथा विभागों को 31 मार्च, 1986 तक मिल जाना चाहिए था ताकि उसका कार्यान्वयन 13 अप्रैल, 1986 से आरम्भ किया जा सकता, जून के अन्त तक प्रकाशित किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह सच है कि राजभाषा की संसदीय समिति का न तो अध्यक्ष है और न उपाध्यक्ष और न ही तीन समितियों में से दो में संयोजक ही है और न ही राजभाषा विभाग इस संबंध में कोई व्यवस्था ही कर रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि टाइपराइटरों जैसी सुविधाएं नहीं है और किसी भी मंत्रालय/विभाग में न तो पर्याप्त संख्या में हिन्दी के टकक है और न ही आशुलिपिक ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार से स्थिति में सुधार करने का विचार रखती है ?